[2015] 1 एस. सी. आर 989

कांदिवली सहकारी औद्योगिक एस्टेट और अन्य

बनाम

महान मुंबई का नगरपालिका निगम और अन्य

(2015 की सिविल अपील संख्या 1431 आदि)

फरवरी 04,2015

[न्यायाधिपति एम. वाई. इकबाल और न्यायाधिपति शिवा कीर्ति सिंह]

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1988 - धारा 368(5) - व्यापार इनकार शुल्क - अधिरोपण - ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.10.2011 द्वारा संशोधित - का औचित्य - आयोजित: अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने की शक्ति है ट्रेड रिफ्यूज चार्ज अपने ट्रेड लाइसेंसधारियों से वसूला जाना है - हालाँकि, वर्ष 2009 से हर साल ट्रेड रिफ्यूज चार्ज को 10% बढ़ाने की अधिसूचना के खंड (6) के तहत प्रावधान मनमाना, दिशानिर्देशों के बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है - इसलिए, प्राधिकरण ने लाइसेंसधारी या ऐसे बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी बढ़े हुए व्यापार इनकार शुल्क की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत – दूसरे पक्ष को सुने ।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों धारा 367, 368, 394 और 479 के संयुक्त पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आयुक्त समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार लाइसेंस प्रदान करते समय शर्तों और प्रतिबंधों को

निर्दिष्ट कर सकते हैं। .आयुक्त ट्रेड लाइसेंसधारकों से वसूले जाने वाले ट्रेड रिफ्यूज शुल्क सहित शुल्कों को अधिसूचित कर सकता है। [पैरा 17] [1005-डी]

2. कानूनी प्रशासन से संबंधित लगभग सभी क़ानूनों में, नगरपालिका अधिकारियों को अनिवार्य रूप से कराधान की शक्ति सौंपी जानी है। शुल्क और शुल्क के संग्रह के मामले में शक्ति के अत्यधिक प्रयोग के प्रश्न पर निर्णय लेते समय योजना के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 23] [1010-एफ-जी]

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी (1954) 1 एससीआर 1005 - संदर्भित।

3. शुल्क मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में किया जाने वाला भुगतान है, लेकिन उन लोगों के लाभ के लिए प्रदान की गई कुछ विशेष सेवाओं या किए गए कुछ विशेष कार्यों के लिए जिनसे भुगतान की मांग की जाती है। दूसरे शब्दों में, कुछ सेवाओं पर विचार करते हुए शुल्क लगाया जाना चाहिए जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से या अनिच्छा से स्वीकार करता है। यह भी आवश्यक है कि मांगी गई फीस या शुल्क उस उद्देश्य के लिए विनियोजित किया जाना चाहिए और अन्य सामान्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विधायिका कर या शुल्क लगाने और उसके संबंध में दर तय करने के लिए अपनी शक्ति वैधानिक प्राधिकारी को सौंप सकती है। अधिकतम दर प्रदान किए बिना स्थानीय निकाय को शक्ति सौंपने वाला अधिनियम अपने आप में प्रतिनिधिमंडल को अत्यधिक या अमान्य नहीं बनाता है। [पैरा 25 और 27] [1011-ई, एफ; 1012-ए, बी]

4. बाध्यता या जबरदस्ती का तत्व सभी अधिरोपणों में मौजूद है, हालांकि अलग-अलग डिग्री में और फीस में यह पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है। मजबूरी इस तथ्य में निहित है कि किसी व्यक्ति की अनिच्छा या सहमति न होने के बावजूद भी

भुगतान कानून द्वारा लागू किया जा सकता है और यह तत्व करों के साथ-साथ फीस में भी मौजूद है। [पैरा 26] [1011-जी]

5. आक्षेपित परिपत्र के खंड (4) में, विशेष व्यवसाय के संबंध में व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने का प्रावधान किया गया है, जो संशोधित व्यापार इनकार शुल्क से सहमत नहीं हैं, वे आवश्यक आवेदन करके और ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं या प्रतिनिधित्व, उन व्यक्तियों को उचित प्रतिक्रिया दी जाएगी, जिनके पास इस आशय की कोई शिकायत है। इसलिए, प्रतिवादी-प्राधिकरण को परिपत्र के खंड (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 29] (1012-एफ-जी)

6. 2009 से हर साल ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में 10% की वृद्धि, जैसा कि आक्षेपित परिपत्र के खंड (6) द्वारा प्रदान किया गया है, अत्यधिक मनमाना और बिना किसी दिशानिर्देश के है। लाइसेंसधारक द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना स्वत: वृद्धि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है। इसलिए, प्रतिवादी लाइसेंसधारी या ऐसे बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना 2009 से किसी भी बढ़े हुए व्यापार इनकार शुल्क की वसूली नहीं करेगा। वास्तविक वृद्धि भविष्य में सुनिश्चित की जा सकती है और महसूस की जा सकती है, लेकिन लाइसेंसधारी या उक्त बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं। [पैरा 30 और 31) [1012-एच; 1013-ए-बी]

डोरान बोमनजी घडियाली बनाम जमशेद कांगा और अन्य एआईआर 1992 में जन्मे। 13; अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावल/ए, (1992)3 एससीसी 285: 1992 (3) एससीआर 328; गुसा मॉडर्न ब्रुअरीज बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2007) 6 सेकंड 317: 2001 (5) एससीआर 343; लीलाबाई

गजानन पंसारे बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2008) 9 एससीसी 720: 2008 (12) एससीआर 248; कंज्यूमर ऑनलाइनफाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2011) 5 एससीसी 360: 2011 (5) एससीआर 911; बी. सी. बनर्जी एवं अन्य बनाम स्टेटऑफ़ एम.पी. एवं अन्य. (1970) 2 एससीसी 467: 1971 (1) एससीआर 844; कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड अन्य बनाम लिबर्टी सिनेमा, असम (1965) 2 एससीआर 477; गुलाबचंद बापालाल मोदी बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद सिटी (1971) 1 एससीसी 82: 2011 (13) एससीआर 26; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नितदीप टेक्सटाइल प्रोसेसर्स (पी) लिमिटेड (2012) 1एस ईसी 226 - उद्धृत।

वाद कानून संदर्भित

ए आई आर 1992 बीओएम	उद्धृत	पैरा 11
1992 (3) एससीआर 328	उद्धृत	पैरा 11
2007 (5) एससीआर 343	उद्धृत	पैरा 11
2008 (12) एससीआर 248	उद्धृत	पैरा 11
2011 (5) एससीआर 911	उद्धृत	पैरा 12(vi)
(1965) 2 एससीआर 477	उद्धृत	पैरा 12(vi)
1971 (1) एससीआर 844	उद्धृत	पैरा 12(vi)
2011 (13) एससीआर 26	उद्धृत	पैरा 12(vi)
2012) 1 सेकंड 226	उद्धृत	पैरा 13
(1954) 1 एससीआर 1005	संदर्भित	पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1431/2015

2013 की रिट याचिका संख्या 1263 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.07.2013 से।

साथ

2015 की सिविल अपील संख्या 1433, 1436, 1434 और 1435

अपीलकर्ताओं के लिए श्याम दीवान, चंदर उदय सिंह, जतिन झवेरी, नीलकमल मिश्रा, सोमनाथ पधान (अनघा एस.देसाई के लिए), प्रताप वेणुगोपाल, सोनल दोशी, सुरेखा रमन, गौरव नायर (के.जे. जॉन एंड कंपनी के लिए)।

प्रतिवादियों की ओर से एल. नागेश्वर राव, एएसजी, जे.जे. जेवियर, भार्गव वी.देसाई, विशालचौधरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति एम. वाई. इकबाल

1. अनुमति स्वीकृत।

2. ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 30.7.2013 के खिलाफ निर्देशित हैं।

3. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा 12 दिसंबर, 2011 के परिपत्र को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रतिवादी-नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा जारी अनुसूची में की गई संबंधित प्रविष्टियों को भी खारिज कर दिया। इससे जुडी अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियाँ, जिससे 'व्यापार इनकार शुल्क' लगाने और उसकी दरों पर सवाल उठाया गया है।

4. अपीलकर्ता व्यापारी हैं, जो गोदाम के रखवाले, गोदाम के रखवाले, बैंक मुकादम, भंडार के वाहक, सामग्री और सामान के भंडारण और कीड़ों, चींटियों, कृंतकों, नमी, बारिश, गर्मी, आग आदि से सुरक्षित रखने की गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

इस प्रयोजन के लिए, अपीलकर्ता समय-समय पर मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (संक्षेप में, 'एमएमसी अधिनियम') की धारा 394 के तहत जारी व्यापार लाइसेंस प्राप्त करते रहे हैं। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदाता 'व्यापार' की वसूली करते हैं वार्षिक आधार पर एमएमसी अधिनियम के तहत व्यापार लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए उसके भुगतान को एक शर्त बनाकर 'अस्वीकार शुल्क' (इसके बाद 'टीआरसी' के रूप में संदर्भित)

5. प्रतिवादी निगम ने परिपत्र दिनांक 5.6.1999 के माध्यम से व्यापार परिसर के मालिकों/कब्जाधारियों से वसूले जाने वाले व्यापार इनकार शुल्क (टीआरसी) का पैटर्न तय किया। व्यापारियों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, नगर आयुक्त ने व्यापार से इनकार करने पर लगाए गए पहले के शुल्कों को संशोधित करने का निर्णय लिया। इसलिए, प्रतिवादी आयुक्त द्वारा 14.1.2008 के एक परिपत्र के माध्यम से 1.1.2008 से टीआरसी को व्यापार लाइसेंस शुल्क का लगभग 300% संशोधित किया गया था। आगे कहा गया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 394 के तहत जारी किए गए लाइसेंस के नवीनीकरण के समय लाइसेंस शुल्क के साथ इसे वर्ष में एक बार एकत्र किया जाना आवश्यक था। अपीलकर्ताओं और कई अन्य दलों ने प्रतिनिधित्व किया और दरों पर पुनर्विचार का आग्रह करने वाली पसंदीदा रिट याचिकाएँ, जिनका उत्तरदाताओं की ओर से यह बयान दिए जाने पर कि वे टीआरसी की दरों पर पुनर्विचार करेंगे, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.4.2010 के एक आदेश द्वारा निपटारा कर दिया था।

6. प्रतिवादी निगम ने अभ्यावेदन पर सुनवाई की और संबंधित विभाग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर कमेटी का गठन किया गया जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने पर,

टीआरसी को दिनांक 12.12.2011 के आक्षेपित परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया। परिपत्र में कहा गया कि टीआरसी 1.1.2008 से पूर्वव्यापी प्रभाव से एकत्र किया जाएगा।

7. यद्यपि व्यापार से इनकार शुल्क वसूलने की दरों में बहुत महत्वपूर्ण कमी आई थी, अपीलकर्ताओं ने असंतुष्ट होकर, रिट याचिकाओं के माध्यम से फिर से बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि वे केवल सुरक्षित अभिरक्षा के प्रयोजनों के लिए ग्राहकों से सामान प्राप्त करते हैं। और निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर ऐसे सामान को उन्हीं शर्तों पर ग्राहकों को लौटाएं। इस उद्देश्य के लिए, वे आग, बारिश, पानी आदि के खिलाफ पर्याप्त स्थान, सुरक्षा और सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में, न तो कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, न ही कोई व्यापार अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इन परिस्थितियों में, यह उनका मामला है कि उन पर टीआरसी लगाना और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी 2008 से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक है। अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि वे कोई व्यापार इनकार उत्पन्न नहीं करते हैं और इसलिए, टीआरसी के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता है।

8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं की रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा टीआरसी लगाने में कुछ भी अवैध, मनमाना, अनुचित या असंवैधानिक नहीं है। यह देखा गया कि यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता 'व्यापार अस्वीकार' उत्पन्न करते हैं या नहीं, तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जिस पर अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

भारत का संविधान. उच्च न्यायालय को इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली कि टीआरसी की वसूली अमान्य है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के अनुसार इसमें 'कुछ के लिए कुछ' का कोई तत्व नहीं है। अपीलकर्ताओं को निश्चित रूप से लाभ हुआ है, क्योंकि उन्हें वर्ष 2008 से कम दरों पर टीआरसी का भुगतान करने के लिए कहा गया है। 12

दिसंबर, 2011 के परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई पूर्वव्यापीता शामिल नहीं है। यदि तर्क बरकरार रखा जाता है, अपीलकर्ताओं को ही उच्चतर टीआरसी का सामना करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने आगे माना है कि एमएमसी अधिनियम की धारा 479 के साथ पठित धारा 368(5) और 394(5) के प्रावधान उत्तरदाताओं को लाइसेंस देने के समय प्रतिबंध और शर्तें लगाने का अधिकार देते हैं। यही सिद्धांत लाइसेंस के नवीनीकरण के चरण पर भी लागू होगा। इस समय, हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के तर्क को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

> "वर्तमान याचिका में अपीलकर्ताओं द्वारा जिस लिंकेज को चुनौती दी गई है, वह टीआरसी की वसूली के तरीके से अधिक चिंतित है, न कि टीआरसी की वसूली के लिए उत्तरदाताओं की क्षमता से। इस तरीके पर निर्णय लेते समय, हम एक बार फिर इस राय पर हैं कि यह एक नीतिगत मामला है और ऐसी नीति के निर्माण में उत्तरदाताओं को पर्याप्त खुली छूट देने की आवश्यकता है। उत्तरदाताओं का यह कहना सही है कि उत्पन्न 'व्यापार अपशिष्ट' की सटीक मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान की निगरानी करना संभव नहीं है। इसलिए उत्तरदाताओं का यह तर्क भी सही है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के चरण में टीआरसी की वसूली करने वाले उत्तरदाताओं में कुछ भी अवैध, मनमाना या असंवैधानिक नहीं है। स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए कथनों से यह प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं का हमेशा से यही तरीका रहा है टीआरसी एकत्र करते रहे हैं। नीति के मामलों में, केवल इसलिए कि संग्रह की कोई अन्य प्रणाली बेहतर हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं है। जब तक यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि संग्रह का तरीका प्रथम दृष्टया, बेतुका, अनुचित या असंगत

रूप से दमनकारी है, हम लिंकिंग के संबंध में सातवीं चुनौती को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। हमें उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई नीति या टीआरसी के संग्रह के तरीके में कुछ भी बेतुका, अनुचित या असंगत रूप से दमनकारी नहीं मिला।"

9. व्यथित होकर, अपीलकर्ता दिनांक 30.7.2013 को रिट याचिकाओं के एक बैच में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं।

10. 2013 की एसएलपी संख्या 30485 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने दिनांक 11.10.2011 के आक्षेपित परिपत्र को अवैध, अधिकारातीत और असंवैधानिक बताया। विद्वान वकील का कहना है कि प्रतिवादी संविधान की धारा 265 के तहत कानून के अधिकार के बिना किसी भी कर, उपकर या अनिवार्य वसूली की मांग, उद्ग्रहण या वसूली नहीं कर सकते हैं। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 368(5) आयुक्त को इसे ठीक करने का अधिकार देती है, शुल्क केवल तभी लगाया जाता है जब व्यापार परिसर का मालिक या अधिभोगी इस संबंध में आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से व्यापार कचरा जमा करने की अनुमति मांगता है और आयुक्त द्वारा ऐसी अनुमति दी जाती है। यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता के किसी भी सदस्य ने कभी भी आयुक्त से ऐसी अनुमति नहीं मांगी थी और इसलिए, अधिनियम की धारा 368(5) के तहत व्यापार इनकार शुल्क लगाने का सवाल ही नहीं उठता। विद्वान वकील के अनुसार कोई भी अनिवार्य वसूली, चाहे वह शुल्क हो या कर या कोई अन्य लेवी हो, कानून द्वारा समर्थित होनी चाहिए। ट्रेड रिफ्यूज शुल्क लगाने वाला दिनांक 12.12.2011 का परिपत्र अतार्किक और मनमाना है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि टीआरसी की वसूली डोरान बोमनजी घडियाली बनाम जमशेद कांगा और अन्य एआईआर 1992 बॉम्बे पृष्ठ

13 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने माना है कि एकमात्र आरोप व्यापारियों पर अधिनियम की धारा 368(5) के तहत प्रदान की गई सीमित सीमा तक लगाया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 479 द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क अधिनियम के तहत आवश्यक किसी भी उद्देश्य के लिए लाइसेंस या लिखित अनुमति से संबंधित होना चाहिए और इसलिए, यह शुल्क केवल किसी विशेष स्थान पर अस्थायी रूप से व्यापार कचरा जमा करने की अनुमति के लिए हो सकता है और होगा यह उन व्यापारियों पर लागू नहीं होगा जो किसी भी स्थान पर अपना कचरा डंप करने की ऐसी अनुमति नहीं मांग रहे हैं। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि जिस तरह से अधिनियम की धारा 368(5) के तहत आरोप लगाने या लगाने पर विचार किया गया है वह अधिकारातीत है। विद्वान वकील ने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमारजयंतीकुमार पासावाला (1992) 3 एससीसी 285 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया। जिसका बाद में गुप्ता मोडेम ब्रुअरीज बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2007) 6 एससीसी 317 और लीलाबाई गजानन पानसरे बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2008) 9 एससीसी720 के मामले में पालन किया गया।

2. नगर निगम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद एसएलपी (सी) संख्या 35558,35589 और 35593 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री चंदर उदय सिंह ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं: -

(i) अपीलकर्ता वेयरहाउसिंग व्यवसाय में लगे हुए हैं और वे कोई व्यापार कचरा उत्पन्न नहीं करते हैं, इस प्रकार प्रतिवादियों को टीआरसी लगाने का अधिकार है। न ही वे कोई विनिर्माण गतिविधि संचालित कर रहे हैं जिसके कारण ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो सकता है और इसलिए, टीआरसी शब्द की गलत व्याख्या की गई है और इसे कचरे के बराबर

कर दिया गया है। यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता केवल सुरक्षित अभिरक्षा के उद्देश्य से ग्राहकों से सामान प्राप्त करते हैं और निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर, ग्राहकों को उसी स्थिति में सामान लौटा देते हैं। इसलिए, प्रतिवादी हर प्रकार के कचरे को 'व्यापार इनकार' के रूप में मानने और उक्त गलत आधार पर अपीलकर्ताओं पर टीआरसी लगाने में गलत हैं। 'व्यापार इनकार' का अर्थ विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल उद्योग द्वारा उत्पन्न कुछ ठोस अपशिष्ट होना चाहिए और इस संबंध में निर्भरता धारा 367 के उप-खंड (ए) और (बी) और उप-धारा (1) और (5) पर रखी गई है। एमएमसी अधिनियम की धारा 368 में और चूंकि "इनकार" और "व्यापार इनकार" शब्दों को अलग-अलग निपटाया गया है, यह संकेत है कि हर प्रकार के इनकार को "व्यापार इनकार" के रूप में योग्य नहीं माना जा सकता है।

(ii). यह बताया गया कि उत्तरदाताओं की गोदामों की स्वयं की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उन गोदामों ने केवल धूल, पेड़ की पत्तियां इत्यादि उत्पन्न कीं और केवल डेढ़ से दो टोकरी की मात्रा में। इसे, किसी भी हद तक, व्यापार का कचरा नहीं माना जा सकता क्योंकि धूल और पेड़ की पत्तियाँ हवा द्वारा गोदामों में उड़ जाती हैं और गोदाम मालिकों/अपीलकर्ताओं द्वारा की जा रही किसी गतिविधि के कारण नहीं। इसके अलावा, एमएमसी अधिनियम की धारा 370 के तहत यह शहर के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी परिसर के कब्जे वाले पर निर्भर होगा जिसके लिए आयुक्त ने धारा 142 (ए) के तहत सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया है और जिसमें कोई पानी की कोठरी नहीं है या नगर निगम की नालियों से जुड़ी गोपनीयता, सभी मलमूत्र और प्रदूषित पदार्थों को एकत्र करने और धारा 367 (बी) के तहत इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए निकटतम पात्र/डिपो तक पहुंचाने के लिए, न कि (ए) प्रासंगिक रूप से 367 (ए) धूल, राख से संबंधित है कूड़ा-कचरा और 367 (बी) व्यापार कूड़ा-कचरा से संबंधित है। इस प्रकार "व्यापार से इनकार" अप्रिय इनकार है और इसे किसी भी व्यापार/व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उत्पन्न कचरे के बराबर नहीं माना जा सकता है और

न ही इसकी तुलना की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया है और अपीलकर्ताओं पर टीआरसी को गैरकानूनी तरीके से लगाने की मांग की जा रही है, जो "व्यापार से इनकार" बिल्कुल भी नहीं करते हैं।

(iii). विद्वान वकील का यह तर्क था कि अपीलकर्ता, जो वेयरहाउसिंग व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई भी व्यापार इनकार उत्पन्न नहीं करते हैं और यदि टीआरसी एक 'कर' का गठन करता है तो टीआरसी के रूप में कर लगाने के लिए कर योग्य घटना नहीं है। वैकल्पिक रूप से यदि टीआरसी को 'शुल्क' माना जाता है, तो, इस परिस्थिति के कारण कि अपीलकर्ता कोई व्यापार इनकार उत्पन्न नहीं करते हैं, 'कुछ के लिए कुछ' का कोई तत्व नहीं है और इसलिए टीआरसी के रूप में शुल्क लगाना अवैध और अमान्य है।

(iv). यह प्रस्तुत किया गया था कि एमएमसी अधिनियम की धारा 394 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ भुगतान को जोड़ना अवैध, अमान्य है और इसलिए, एमएमसी अधिनियम की धारा 394 के तहत व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण दिया जाना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। अपीलकर्ता टीआरसी का भुगतान करते हैं या नहीं। एमएमसी अधिनियम की धारा 394 के तहत व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क के अलावा टीआरसी लगाया जा रहा है, इसमें दोगुना शुल्क लगाया जाता है, जो पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है और विशेष रूप से अपीलकर्ताओं के लिए कानून के अधिकार के बिना है, जो उत्पन्न नहीं करते हैं। कोई भी 'व्यापार अस्वीकार'। इसलिए, यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि टीआरसी की लेवी और संग्रहण को वेयरहाउसिंग गतिविधि के संचालन के लिए अपीलकर्ताओं को दिए गए वार्षिक व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है, जब इस तरह के लिंकेज को सक्षम करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है; और तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वव्यापी शुल्क या शुल्क लगाने के लिए किसी विशिष्ट प्राधिकारी की

अनुपस्थिति में, प्रतिवादी नंबर 1 1.1.2008 से टीआरसी नहीं लगा सका, जब प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय को एक गंभीर आश्वासन दिया गया था कि ऐसा होगा नवीनीकरण के चरण में टीआरसी और लाइसेंस शुल्क के बीच कोई संबंध नहीं है। एमएमसी अधिनियम की धारा 471 के तहत, प्रतिवादी नंबर 1 धारा 368 (1) से (4) के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने का हकदार है और अधिनियम की धारा 472 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 उल्लंघन में अपराध जारी रखने के लिए जुर्माना लगाने का हकदार है· धारा 368 (1) से (5) के किसी भी प्रावधान का। जब अधिनियम के तहत दंड प्रावधान प्रदान किए जाते हैं, तो टीआरसी का भुगतान बिना किसी आधार या औचित्य के किया गया है, जिसे ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण से जोड़ने की मांग की गई है, जो कानून में अनुचित और खराब है। इसके अलावा, केवल वैध ट्रेड लाइसेंस धारकों से ही टीआरसी लिया जा रहा है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो जाता है कि 1976 के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में वेयरहाउसिंग लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। इसलिए, टीआरसी पर बोझ केवल वैध लाइसेंस धारकों पर लागू किया जा रहा है, न कि अन्य लोगों पर जो बिना किसी लाइसेंस के व्यापार कर रहे हैं।

(v). यह फिर से बताया गया कि प्रतिवादियों ने अपने स्वयं के परिपत्र संख्या सीएच/280/ एसडब्ल्यूएम दिनांक 06.04.2010 को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2010 के लिए, टीआरसी जारी किए गए लाइसेंस की लाइसेंस फीस के आधार पर लगाया जाएगा। एमएमसी की दुकानें एवं स्थापना विभाग और प्रतिवादी ऐसा करेंगे भविष्य में टीआरसी को लाइसेंस फीस से अलग कर दिया जाएगा और नया टीआरसी लेवी पैटर्न पेश किया जाएगा। टीआरसी अब गलत तरीके से वर्ग मीटर के आधार पर वसूला जाता है। परिसर के क्षेत्र का फुटेज वास्तव में लाइसेंस शुल्क से अधिक है जो पूरी तरह से अतार्किक, तर्कहीन, मनमाना और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई नीति और टीआरसी के संग्रह का तरीका (चाहे कर्मचारियों की संख्या या वर्ग मीटर क्षेत्र के आधार

पर शुल्क लिया जाए) बेतुका, अनुचित और अनुपातहीन रूप से दमनकारी है, बिना सोचे-समझे और अक्षम और कानून के अधिकार के बिना।

(vi). अंत में, यह तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा कर या उपकर के लिए धन का कोई भी अनिवार्य निष्पादन सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए और इसके लिए एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए और इसमें इरादे के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ भी नहीं होना चाहिए पढ़ें या कुछ भी निहित न करें और किसी को इस्तेमाल की गई भाषा पर निष्पक्षता से गौर करना चाहिए। हमारा ध्यान उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2011)5 एसईसी 360 में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया गया था। इस संबंध में यह मांग की गई थी यह बताया जाना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लेवी/शुल्क लगाना एक कर की प्रकृति में है, न कि शुल्क और इसलिए क़ानून के समर्थन के बिना ऐसा लगाना अनुचित और अनुचित है।विद्वान वकील ने हमारा ध्यान गुप्ता मॉडर्न ब्रुअरीज बनाम स्टेट ऑफ जेएंडके और अन्य (2007) 6 एससीसी 317 और बीसी बनर्जी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ एमपी और अन्य (1970) 2 एससीसी 467 के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों की ओर भी आकर्षित किया।

13. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एल. नागेश्वर राव ने सबसे पहले तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 368(5) की संवैधानिक वैधता को किसी भी अपीलकर्ता द्वारा संविधान के अधिकार के बाहर होने के कारण कभी चुनौती नहीं दी गई। अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाओं में केवल उत्तरदाताओं को दिनांक 14.1.2008 और 11.10.2011 के परिपत्रों को रद्द करने और/या वापस लेने और 9 जून, 2014 के नोटिस को वापस लेने का निर्देश देने वाली उचित रिट जारी करने की प्रार्थना की है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने यह तर्क देकर परिपत्र को चुनौती दी कि व्यापार से इनकार शुल्क एकत्र करने का तरीका कानून के विपरीत था। टीआरसी की मांग करने और लगाने की प्राधिकरण की क्षमता को

किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई है। शुल्क/टीआरसी और कर लगाने में अंतर करते हुए, विद्वान वकील ने आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम शिरूर मठ के श्रीलक्ष्मिन्द्र तीर्थ स्वामी, (1954) 1 एससीआर 1005 के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुपात पर भारी भरोसा जताया। श्री राव ने कोर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि उसमें दिए गए दिशानिर्देशों की वैधता का किसी भी आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड एएनआर बनाम लिबर्टी सिनेमा, असम (1965) 2 एससीआर 477 के मामले में एक निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान वकील ने संग्रह के उद्देश्य और उद्देश्य पर भी दलील दी और कहा कि इस उद्देश्य के लिए पूर्ण समानता असंभव है। शुल्क या शुल्क लगाने का. विद्वान वकील ने गुलाबचंद बापलाल मोदी बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद सिटी, (1971) 1 एससीसी 82 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम निटडिप टेक्सटाइल प्रोसेसर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 1 एसईसी 226 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

14. पार्टियों द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने से पहले, हम बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1988 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे। धारा 3 (वाय वाय) 'व्यापार इनकार' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

> "3(वाय वाय) "व्यापार कचरा" का अर्थ है और इसमें किसी भी व्यापार, निर्माण या व्यवसाय का कचरा शामिल है।"

15. धारा 367 आयुक्त को व्यापार अपशिष्ट सहित अपशिष्ट पदार्थों के अस्थायी जमा या अंतिम निपटान के लिए पात्र, डिपो और स्थान प्रदान करने का प्रावधान करने का अधिकार देती है। धारा 367 यहां नीचे उद्धृत की गई है:-

> "367. कूड़ेदानों, डिपो और कूड़े आदि के लिए स्थानों का प्रावधान और नियुक्ति,

आयुक्त उचित और सुविधाजनक स्थितियों में अस्थायी जमा या निपटान के लिए सार्वजनिक पात्र, डिपो और स्थान प्रदान करेगा या नियुक्त करेगा।

(ए) धूल, राख, कचरा और कूड़ा;

(बी) व्यापार से इनकार;"

16. धारा 368 धूल आदि इकट्ठा करने और जमा करने के प्रयोजन के लिए मालिकों और कब्जाधारियों के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान बताती है। धारा 368, 394 और 479, जो इन अपीलों में विचाराधीन हैं, इस प्रकार पढ़ें: "368. धूल आदि एकत्र करने और जमा करने के लिए मालिकों और कब्जाधारियों का कर्तव्य,

(1) सभी परिसरों के मालिकों और अधिभोगियों पर यह दायित्व होगा कि वे अपने संबंधित परिसरों से सभी धूल, राख, कूड़ा-कचरा और व्यापार से इनकार कर दें और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आयुक्त के समक्ष ऐसे समय में जमा कराएं। समय-समय पर सार्वजनिक पात्र, डिपो या अंतिम पूर्ववर्ती धारा के तहत प्रदान या नियुक्त किए गए स्थान या उसके अस्थायी जमा या अंतिम निपटान को निर्धारित करता है

(2) .... ..

(3) ..... .

(4)-..... ..

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यापार परिसर का मालिक या अधिभोगी, परिसर से प्रतिदिन या समय-समय पर एकत्र किए गए व्यापार कचरे को अस्थायी रूप से आयुक्त द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए किसी स्थान पर जमा करने की अनुमति चाहता है, तो आयुक्त ऐसा कर सकता है। , आवेदन पर, और ऐसे शुल्कों

के भुगतान पर, जो आयुक्त समय-समय पर तय कर सकते हैं, आवेदक को तदनुसार व्यापार इनकार जमा करने की अनुमति देते हैं।"

"394. कुछ वस्तुओं (या जानवरों) को नहीं रखा जाना चाहिए, और कुछ व्यापार, प्रक्रियाएं और संचालन बिना लाइसेंस के नहीं किए जाने चाहिए; और खतरे या उपद्रव को रोकने के लिए जब्त की जाने वाली चीजों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, आदि।-

(1) आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार छोड़कर, कोई भी व्यक्ति-

(ए) किसी भी परिसर में या उस पर रखना, या पीड़ित होना या रखने की अनुमति देना,

(I) अनुसूची एम के भाग । में निर्दिष्ट कोई भी लेख; या,

(II) अनुसूची एम के भाग ॥ में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु, उसमें अधिकतम मात्रा के रूप में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक है या जहां ऐसी वस्तु उस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अन्य वस्तु या वस्तुओं के साथ रखी जाती है, ऐसी अन्य अधिकतम मात्रा जो अधिसूचित की जा सकती है आयुक्त द्वारा) ऐसी वस्तु का, जिसे किसी भी समय एक ही परिसर में या उसके ऊपर बिना लाइसेंस के रखा जा सकता है;

(बी) अनुसूची एम के भाग III में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को बिक्री के लिए या घरेलू उपयोग के अलावा किसी भी परिसर में या उस पर रखने या रखने की अनुमति नहीं देगा;

(सी) .....

(डी).....

(ई) किसी भी परिसर में या उसके ऊपर ले जाना या ले जाने की अनुमति देना या सहना।-

(I) अनुसूची एम के भाग IV में निर्दिष्ट कोई भी व्यापार, या ऐसे किसी भी व्यापार से जुड़ी कोई प्रक्रिया या संचालन;

(II) कोई भी व्यापार, प्रक्रिया या संचालन, जो आयुक्त की राय में, जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है, या अपनी प्रकृति से या जिस तरीके से, या शर्तों के तहत उपद्रव पैदा करने की संभावना है , वही है, या होने का प्रस्ताव है

आगे ले जाना;

(एफ) किसी वाहक के व्यापार या संचालन के लिए [बृहन्न मुंबई] के भीतर ले जाना या किसी परिसर का उपयोग करना या उपयोग करने की अनुमति देना।

(2).....

(3).....

(4) ..... .

(5) यह आयुक्त के विवेक पर होगा.-

(ए) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी लाइसेंस को ऐसे प्रतिबंधों या शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन देने के लिए, जिसे वह निर्दिष्ट करना उचित समझे, या (बी} सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, रोकना ऐसा कोई भी लाइसेंस:

बशर्ते कि, आयुक्त ऐसे किसी भी लाइसेंस को रोकते समय ऐसे रोक के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और संबंधित व्यक्ति

को अपने आदेश की एक प्रति देगा जिसमें ऐसे रोक के कारण शामिल होंगे:

बशर्ते कि, इस उपधारा के तहत आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

"479. शर्तों आदि को निर्दिष्ट करने के लिए लाइसेंस और लिखित अनुमति, जिस पर उन्हें प्रदान किया जाता है: -

(1) क्या इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि लाइसेंस या लिखित अनुमति लाइसेंस किसी भी उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है, ऐसे लाइसेंस या लिखित अनुमति में क्या निर्दिष्ट किया जाएगा। अवधि जिसके लिए, और प्रतिबंध और शर्तें जिनके अधीन, इसे प्रदान किया जाता है, और इसे प्रदान करने के लिए धारा 68 के तहत सशक्त आयुक्त या नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत दिया जाएगा।

(2).....

(3)..·.....

(4....."

17. यहां पहले उद्धृत प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आयुक्त समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार लाइसेंस प्रदान करते समय शर्तों और प्रतिबंधों को निर्दिष्ट कर सकता है। आयुक्त ट्रेड लाइसेंसधारियों से वसूले जाने वाले ट्रेड रिफ्यूज शुल्क सहित शुल्कों को अधिसूचित कर सकता है।

18. एमएमसी अधिनियम के तहत आयुक्त को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 14.1.2008 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें टीआरसी को व्यापार लाइसेंस शुल्क का लगभग 300 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, इस शर्त के साथ कि टीआरसी नवीनीकरण के समय एकत्र किया जाएगा। अधिनियम की धारा 394 के तहत लाइसेंस दिसंबर, 2009 में समाप्त होने वाला था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 14.1.2008 के उक्त परिपत्र को रिट याचिकाओं के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। जब रिट याचिकाएं सुनवाई के लिए ली गईं, तो प्रतिवादी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अदालत को सूचित किया कि व्यापार इनकार शुल्क की दर पर प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। निगम के वकील द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर, व्यापारियों की शिकायतें संतुष्ट होने पर रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया।

19. दिसंबर, 2011 में, पूर्व परिपत्र में तय टैरिफ पर पुनर्विचार के बाद उत्तरदाताओं ने 11.10.2011 को एक और परिपत्र जारी किया, जिसके तहत टीआरसी दर को 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था। इसमें संलग्न संशोधित दरों के अवलोकन से पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के संबंध में दरें काफी कम कर दी गई हैं। संशोधित दरों को उद्धृत करने के बजाय हम यहां दिनांक 11.10.2011 के संशोधित परिपत्र को नीचे उद्धृत करना चाहेंगे। परिपत्र का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:-

"ग्रेटर मुंबई नगर निगम

(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग)

सं. पीआरए . ए/11384/एसडब्ल्यूएम

दिनांक 11.10.2011

परिपत्र

विषय:-: ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में संशोधन/संशोधन।

ग्रेटर मुंबई नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग द्वारा ट्रेड रिफ्यूज शुल्क की वसूली के उद्देश्य से, महापौर परिषद ने संकल्प संख्या 14 दिनांक 15.4.99 के माध्यम से उक्त शुल्क को लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क के कुछ गुणा में बिना किसी शुल्क के वसूल करने की मंजूरी दे दी। व्यवसाय की श्रेणी उस प्रक्रिया के अनुसार, (1) लाइसेंसिंग विभाग (2) दुकानें और स्थापना विभाग (3) स्वास्थ्य विभाग और को जिम्मेदारी सौंपने के संबंध में परिपत्र प्रा.ए./17785/एसडब्ल्यूएम दिनांक 14.1.2008 के माध्यम से आदेश जारी किए गए थे। (4) बाजार विभाग, कचरे के निपटान और लाइसेंसिंग/पंजीकरण शुल्क के गुणन के लिए किए गए खर्चों को सह-संबंधित करके और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय 'व्यापार इनकार शुल्क' की वसूली करने और उसे 'विविध शुल्क' के तहत जमा करने के लिए भी। 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के वित्तीय बजट प्रमुख के अंतर्गत आय का।

हालाँकि, ट्रेड रिफ्यूज चार्ज के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदन के साथ-साथ कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, 1) लाइसेंसिंग विभाग, दुकानें और स्थापना विभाग (3) स्वास्थ्य विभाग और (4) मार्केट के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

विभाग और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए व्यापारियों से ट्रेड रिफ्यूज चार्ज के संबंध में जांच की गई। सभी विभाग स्तरों से प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया तथा व्यवसाय पर लगाये जाने वाले ट्रेड रिफ्यूज चार्ज, उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण हेतु किये जाने वाले व्यय आदि पहलुओं की जांच की गयी तथा तद्नुसार मा.नगर आयुक्त ने क्रमांक एमजीसी/एफ/5874 दिनांक 2.9.2011 के तहत तदनुसार ट्रेड रिफ्यूज चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है और निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

(1) चूंकि दुकान एवं स्थापना विभाग द्वारा अपशिष्ट उत्पादन के अनुपात में ट्रेड रिफ्यूज चार्ज लगाया जा रहा है, इसलिए इसे परिपत्र क्रमांक प्रा.ए./6123 दिनांक 05.06.1999 के अनुसार जारी रखा जाएगा।

(2) जिन व्यवसायों के लिए ट्रेड रिफ्यूज चार्ज अधिक होने की शिकायतें हैं और जिनके संबंध में वर्ष 2008 से उनके अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में परिवर्तन किए गए हैं, उन्हें 'अनुसूची बी-1' में दर्शाया गया है। ".

(3) विवाह और पार्टियों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल के लिए ट्रेड रिफ्यूज चार्ज अब शुरू किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों के हॉलों और हाउसिंग सोसाइटियों के लेआउट आर.जी.प्लॉट्स के कार्यों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, वाणिज्यिक कर में शामिल नहीं है।

(4) उन व्यवसायों के संबंध में जो संशोधित ट्रेड रिफ्यूज चार्ज से सहमत नहीं हैं, उनसे संलग्न प्रारूप में आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं और उसकी जांच करने के बाद संबंधित सहायक को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। इंजीनियर (एस.डब्ल्यू.एम.) को मुख्य अभियंता (एस.डब्ल्यू.एम.) को प्रस्तुत करने हेतु।

(5) जिस व्यवसाय के संबंध में एक से अधिक लाइसेंस हैं, उस लाइसेंस पर ट्रेड रिफ्यूज चार्ज लगाया जाएगा, जिसकी फीस अन्य लाइसेंसों से अधिक है।

(6) वर्ष 2009 से हर साल ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।

(7) जिन व्यवसायों ने सर्कुलर में उल्लिखित दर से कम/अधिक दर पर ट्रेड रिफ्यूज चार्ज का भुगतान किया है, उन्हें 2008 से अगले वर्ष से ट्रेड रिफ्यूज टैक्स की वसूली के समय समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यवसाय के संबंध में जिनके ट्रेड रिफ्यूज चार्ज की दरों में वृद्धि/कमी नहीं की गई है या जिन व्यवसायों ने अभी तक ट्रेड रिफ्यूज चार्ज का भुगतान नहीं किया है, उनसे 2008 के परिपत्र में दर्शाई गई दर पर तुरंत इसकी वसूली की जानी चाहिए।

सभी संबंधित विभाग प्रमुख इस परिपत्र का संज्ञान लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।

एसडी/-

मुख्य अभियंता (एस.डब्ल्यू.एम.)

11.10.11.

लाइसेंसिंग अधीक्षक।"

20. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करते हुए निष्कर्ष निकाला कि एमएमसी अधिनियम प्रतिवादियों के अधिकारियों को व्यापार लाइसेंस देने के समय शर्तें लगाने और व्यापार इनकार शुल्क वसूलने की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय ने कहा:

> "21. एमएमसी अधिनियम की धारा 479 के साथ पठित धारा 368(5) और 394(5) के प्रावधान, हमारे विचार में, लाइसेंस देने के समय प्रतिवादियों को प्रतिबंध और शर्तें लगाने का अधिकार देते हैं। वही सिद्धांत लागू होगा यहां तक कि लाइसेंस के नवीनीकरण के चरण में भी। वर्तमान याचिका में अपीलकर्ताओं द्वारा जिस लिंकेज को चुनौती दी गई है, वह टीआरसी की वसूली के तरीके से अधिक चिंतित है, न कि उत्तरदाताओं की टीआरसी की वसूली करने की क्षमता से। तरीका तय करने में, हम एक बार फिर से हैं राय है कि यह एक नीतिगत मामला है और ऐसी नीति के निर्माण में उत्तरदाताओं को पर्याप्त छूट दी जानी आवश्यक है। उत्तरदाताओं का यह कहना सही है कि सटीक मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान की निगरानी करना संभव नहीं है और उत्पन्न 'व्यापार अपशिष्ट' की गुणवत्ता। इसलिए उत्तरदाताओं का यह तर्क भी सही है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के चरण में टीआरसी की वसूली करने वाले उत्तरदाताओं

में कुछ भी अवैध, मनमाना या असंवैधानिक नहीं है। स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा हमेशा से ही टीआरसी एकत्र करने का यही तरीका रहा है। नीति के मामलों में, केवल इसलिए कि संग्रह की कोई अन्य प्रणाली बेहतर हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं है। जब तक यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि संग्रह का तरीका प्रथम दृष्टया, बेतुका, अनुचित या असंगत रूप से दमनकारी है, हम लिंकिंग के संबंध में सातवीं चुनौती को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। हमें उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई नीति या टीआरसी के संग्रह के तरीके में कुछ भी बेतुका, अनुचित या असंगत रूप से दमनकारी नहीं मिला।

22. हम पहले ही मान चुके हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा टीआरसी लगाने में कुछ भी अवैध, मनमाना, अनुचित या असंवैधानिक नहीं है। इन परिस्थितियों में, हम अपीलकर्ताओं की सहायता के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं, जो टीआरसी के भुगतान को स्थगित करना या टालना चाहते हैं और साथ ही नवीनीकृत लाइसेंस के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं। नवीनीकरण की मंजूरी मिलने पर, एमएमसी को टीआरसी की वसूली के लिए नई कार्यवाही शुरू करनी होगी, जिससे अपीलकर्ताओं को इसके भुगतान में विरोध करने या देरी करने का मौका मिलेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।"

21. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 368(5) की संवैधानिक वैधता को रिट याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है। उन सभी रिट याचिकाओं में आक्षेपित परिपत्र द्वारा व्यापार इनकार शुल्क तय करने और मांगने की आयुक्त की शक्ति पर सवाल उठाया गया है। जो इन अपीलों का विषय है। एकमात्र चुनौती परिपत्र दिनांक 11.10.2011 और उसके साथ संलग्न अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियाँ हैं, जो उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर जारी की गई हैं कि परिपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित दर पूरी तरह से अतार्किक और मनमानी है। द्वारा किया गया मुख्य विवाद

अपीलकर्ताओं का कहना है कि वे कोई भी व्यापार अस्वीकार उत्पन्न नहीं करते हैं और इसलिए, टीआरसी लगाने के लिए निर्धारित दर मनमानी, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।

22. चूंकि अधिनियम की धारा 368 सहित विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए हम उक्त प्रावधानों के दायरे में जाना जरूरी नहीं समझते हैं। एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या दिनांक 11.10.2011 के आक्षेपित परिपत्र द्वारा लगाई गई फीस या शुल्क उचित और उचित है या मनमानी से ग्रस्त है।

23. स्थापित कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कानूनी प्रशासन से संबंधित लगभग सभी कानूनों में, नगरपालिका अधिकारियों को अनिवार्य रूप से कराधान की शक्ति सौंपी गई है। शुल्क और शुल्क के संग्रह के मामले में शक्ति के अत्यधिक प्रयोग के प्रश्न पर निर्णय लेते समय योजना के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

24. हालाँकि, आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, (1954) 1 एससीआर 1005: एआईआर 1954 एससी 282 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित होगा। जो

हमारे अनुसार अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दीवान और श्री सिंह द्वारा उठाए गए बिंदुओं का संपूर्ण उत्तर होगा। पैरा 44 में, इस न्यायालय ने कहा:

> "44. अब फीस की बात करें तो, 'शुल्क' को आम तौर पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। लगाए गए शुल्क की राशि सरकार द्वारा इसे प्रदान करने में किए गए खर्च के आधार पर मानी जाती है। सेवा हालांकि कई मामलों में लागतों का मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। आम तौर पर, शुल्क एक समान होते हैं और भुगतान करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ताओं की अलग-अलग क्षमताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है (वीडियो लुत्ज़ "सार्वजनिक वित्त" पृष्ठ 215 पर)। ये निस्संदेह कुछ हैं सामान्य विशेषताएं, लेकिन चूंकि विभिन्न प्रकार की फीस हो सकती है, इसलिए ऐसी परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू हो।"

25. शुल्क निस्संदेह, मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में भुगतान है, लेकिन उन लोगों के लाभ के लिए प्रदान की गई कुछ विशेष सेवाओं या किए गए कुछ विशेष कार्यों के लिए जिनसे भुगतान की मांग की जाती है। दूसरे शब्दों में, कुछ सेवाओं पर विचार करते हुए शुल्क लगाया जाना चाहिए जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से या अनिच्छा से स्वीकार करता है। यह भी आवश्यक है कि मांगी गई फीस या शुल्क उस उद्देश्य के लिए विनियोजित किया जाना चाहिए और अन्य सामान्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्विवाद रूप से, विधायिका कर या शुल्क

लगाने और उसके संबंध में दर तय करने के लिए अपनी शक्ति वैधानिक प्राधिकरण को सौंप सकती है।

26. कर और शुल्क के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा कि जबरदस्ती या दबाव का तत्व सभी अधिरोपणों में मौजूद है, हालांकि अलग-अलग डिग्री में और यह शुल्क में पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है। मजबूरी इस तथ्य में निहित है कि किसी व्यक्ति की अनिच्छा या सहमति न होने के बावजूद भी भुगतान कानून द्वारा लागू किया जा सकता है और यह तत्व करों के साथ-साथ फीस में भी मौजूद है।

27. चूंकि अधिनियम की धारा 368(5) के प्रावधान चुनौती के अधीन नहीं हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दीवान और श्री सिंह द्वारा लिए गए निर्णयों का तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। वर्तमान मामला. जैसा भी हो, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकतम दर प्रदान किए बिना स्थानीय निकाय को शक्ति सौंपने वाला एक अधिनियम अपने आप में प्रतिनिधिमंडल को अत्यधिक या अमान्य नहीं बनाता है।

28. विवादित परिपत्र पर वापस आते हुए, यह पता चलता है कि शिकायतों और अभ्यावेदन और व्यापार इनकार शुल्क के संबंध में कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए गए हैं। उक्त परिपत्र के खंड (4) और (6) को यहां पुनः उद्धृत किया गया है: -

> "(4) उन व्यवसायों के संबंध में जो संशोधित ट्रेड रिफ्यूज चार्ज से सहमत नहीं हैं, उनसे संलग्न प्रारूप में आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं और उसकी जांच करने के बाद मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित सहायक अभियंता (एस.डब्ल्यू.एम.) को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। (एस.डब्ल्यू.एम.)।

(6) वर्ष 2009 से ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।"

29. जहां तक खंड (4) का संबंध है, विशेष व्यवसाय के संबंध में ऐसे व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने का प्रावधान किया गया है जो संशोधित व्यापार इनकार शुल्क से सहमत नहीं हैं, वे आवश्यक आवेदन करके प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और ऐसे आवेदन या अभ्यावेदन पर, उन व्यक्तियों को उचित प्रतिक्रिया दी जाएगी, जिनके पास इस आशय की कोई शिकायत है। इसलिए, हम प्रतिवादी प्राधिकारी को परिपत्र के खंड (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देते हैं।

30. परिपत्र के खंड (6) के संबंध में, प्रथम दृष्टया हमारी निश्चित राय है कि 2009 से हर साल व्यापार कचरा शुल्क में 10% की वृद्धि करना अत्यधिक मनमाना और बिना किसी दिशानिर्देश के है। हमारी सुविचारित राय में, लाइसेंसधारी द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना हर साल व्यापार से इनकार शुल्क में 10% की स्वचालित वृद्धि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इसलिए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी लाइसेंसधारी या ऐसे बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना 2009 से किसी भी बढ़े हुए व्यापार इनकार शुल्क की वसूली नहीं करेगा।

31. मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हमें उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिला। हालाँकि, हम विवादित आदेश को केवल यह मानते हुए संशोधित करते हैं कि 2009 से हर साल ट्रेड रिफ्यूज चार्ज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने वाले सर्कुलर का खंड (6) अत्यधिक मनमाना और बिना किसी दिशानिर्देश के है। इसलिए, हमारा मानना है कि वास्तविक वृद्धि या लागत में कमी या लाइसेंसधारी द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति आदि के बावजूद हर साल व्यापार इनकार शुल्क में 10 प्रतिशत की

वृद्धि तर्कसंगतता के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी प्राधिकारी 2009 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए व्यापार इनकार शुल्क की वसूली नहीं करेगा। वास्तविक वृद्धि का पता लगाया जा सकता है और भविष्य में महसूस किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंसधारी या व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं। उक्त बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

32. उपरोक्त संशोधन और निर्देशों के साथ, इन अपीलों का निपटान लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।